फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 73 संख्याः 19 प्रभात जयपुर, शनिवार 20 अगस्त, 2022 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

The call of the mountains comes at a price

Today, I live with full acceptance & gratitude: I am here because the mountains have let me.

SPACE: Origin Of The Moon

CULTURE: Immunity-Boosting Food

A recipie has no soul but the ingredients & culture of food does.

जॉर्जिया में इस बार लॉगरहैड सी टर्टल नैस्टिंग का नया रिकॉर्ड बना है। इस वर्ष तीन अगस्त को यहां टर्टल नैस्ट की गिनती 3,960 पहुंच गई जो कि 33 साल में, अर्थात् 1989 से सर्वे शुरु होने के बाद से, सर्वाधिक थी। वर्ष 2004 में सबसे कम 358 नैस्ट देखे गए थे, उसे देखते हुए नैस्ट की संख्या दस गुना बढ़ गई है। जॉर्जिया सी टर्टल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मार्क डॉड, जो वरिष्ठ वन्यजीव वैज्ञानिक हैं, ने कहा कि लॉगरहैड टर्टल लम्बा जीते हैं और 35 साल की उम्र के बाद प्रजनन कर पाते हैं। जॉर्जिया की लॉगरहैड टर्टल की आबादी को अमेरिका में "खतरे में" माना गया है। हालांकि इनकी आबादी 1990 के बाद से प्रति वर्ष चार प्रतिशत बढ़ी है, पर लक्ष्य हासिल करने में 20 साल और लगेंगे। लगभग 300 पाउण्ड वजनी मादा लॉगरहैड मई से अगस्त के बीच प्रजनन के लिए तट पर आती है और जमीन में गड्ढा करके प्रायः रात में अंडे देती है। यहां जितने भी सी टर्टल घर बनाते हैं, सभी की सुरक्षा और निगरानी जॉर्जिया सी टर्टल कोऑपरेटिव नामक संस्था करती है। संस्था लगभग तीस साल से नैस्टिंग सीज़न के दौरान क्षेत्र की निगरानी कर रही है।

"गैर स्थानीय" निवासियों को मतदान का अधिकार मिलेगा कश्मीर में

इस नयी व्यवस्था से 23 लाख नये वोटर जुड़ेंगे कश्मीर के टोटल 76 लाख मतदाता की सूची में

-श्रीमंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अगस्त। बिहार की राजनीतिक सत्ता के हाथ से जाने और बढ़ती मंहगाई व बेरोजगारी के मुद्दो पर नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रदर्शन को लेकर आम जनता की असहजता से निराश भाजपा गुजरात के आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर कश्मीर मुद्दे का बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार कर सकती है। गुजरात के बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं।

जम्मू और कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हदेश कुमार ने बुधवार को घोषणा की कि अगले वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनावों में राज्य से बाहर के लोगों को भी वोट देने की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि 3 लाख अतिरिक्त वोटर्स का जुड़ना या क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में 30 प्रतिशत वोटर्स बढ़ जाना। इस सूची में वर्तमान में 76 लाख वोटर्स हैं। नए वोटर्स में सैन्य कर्मी, प्रवासी मजदूर और प्राइवेट सैक्टर के कर्मचारी होंगे। यह कदम भाजना के "एक देश-एक संविधान" सिद्धान्त पर फिट बैठता है क्योंकि अपने गृह राज्य के बजाए अन्य राज्यों में रह रहे भारतीय नागरिक कुछ निश्चित मापदण्डों को पूरा करते हैं तो उन्हें वोट देने की अनुमति है। कश्मीर जो कि भारत का एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य राज्य है और जिसने पिछले तीन दशकों में बगावत फेली है, में इसको लेकर चिन्ताएं बढ़ गई हैं, कि केन्द्र सरकार यहां बड़े प्रभावी जनसांख्यिकीय परिवर्तन करना चाहती है। अगस्त 2019 से जब धारा 370 समाप्त की गई, भारत सरकार ने नए आवास कानून सहित कई विधायी कदम उठाए हैं, इनके तहत क्षेत्र में 15 वर्षो से अधिक समय तक निवासरत प्रत्येक भारतीय को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया है। गैर कश्मीरीयों को भी घाटी में जमीन खरीदने के अधिकार दिए गए हैं।

- सेना के जवान व अफसर, माइग्रैंट लेबर तथा प्राइवेट सैक्टर व पब्लिक सैक्टर के कर्मचारी अब कश्मीर में मतदान के अधिकारी होंगे, अगर वे पन्द्रह साल से ज्यादा समय से कश्मीर में रह रहे हैं। इन लोगों को कश्मीर में सम्पत्ति खरीदने का अधिकार भी मिलेगा।
- यह नयी व्यवस्था, जिसकी घोषणा कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने बुधवार को की थी, भाजपा के "एक देश, एक संविधान" सिद्धांत पर आधारित है।
- अतः अगर इस व्यवस्था का भाजपा को कश्मीर के चुनाव में ज्यादा लाभ मिले ना मिले, पर देश में गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, व छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों में जरूर लाभ मिलेगा।
- महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला आदि, कश्मीर के नेताओं ने इसे, "बाहरी वोटर" लाकर कश्मीर में चुनाव जीतने की मोदी सरकार की साजिश बताया।

मोदी सरकार ने पूर्व में राज्य के एक नये चुनावी मानचित्र की घोषणा की थी, जिसमें हिन्दू बाहुल्य जम्मू क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 कर दी गई थी। यद्यपि कश्मीर घाटी में एक ही निर्वाचन क्षेत्र

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'प्रॉफैशनल जीवन में पिछड़ने से रोकने के लिये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल व कॉलेज खोलेंगे'

हिन्दी भाषी छत्तीसगढ़ ने भी बच्चों व युवाओं को अंग्रेजी में पारंगत करने की स्कीम बनायी

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अगस्त। हिन्दी बैल्ट के राज्य छत्तीसगढ़ ने निर्णय लिया है कि उसे अपने युवाओं को व्यवसाय एवं रोज़गार बाजार की प्रतिस्पर्द्धा में खड़ा करने के लिये अंग्रेजी की जरूरत है।

यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार अगले शैक्षणिक सत्र, 2023 से अंग्रेजी माध्यम के 10 कॉलेज खोलेगी। राज्य में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय तो पहले से ही बड़ी संख्या में संचालित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर अपने इस निर्णय की घोषणा करते हुये कहा कि सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को और बढ़ावा देना है।

कई राज्यों ने उनकी सरकारों द्वारा संचालित चयनित स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षण के माध्यम के रूप अंग्रेजी का चयन कर लिया है क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करना आज युवाओं की आम आकांक्षा बन चुका है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ने इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते हुये, कुछ सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शुरु कर दिया था क्योंकि वे चाहते थे कि राज्य के बच्चे प्रतियोगिता के क्षेत्र में पीछे न रहें। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने भी कई साल पहले अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल दिय हैं।

अभी-अभी आंध्र प्रदेश ने भी अपने स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का रूप दे दिया है तथा राज्य सरकार चाहती है कि आगामी कुछ ही वर्षों में राज्य के सभी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बन जायें। राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इस प्रोजैक्ट में निजी रुचि ली है तथा राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य विद्यार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों तथा कैरियर निर्माण के अवसरों के लिए पूरी तरह तैयार करना तथा उन्हें वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित होने में समर्थ बनाना है। अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की माँग समाज के सभी वर्गों, खासतौर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की ओर से आती रही है।

श्री वास्तव ने कहा कि लेकिन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी- विभिन्न विषयों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने में सक्षम शिक्षकों और व्याख्याताओं की तलाश। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि विभिन्न सरकारी कॉलेजों के मौजूदा शिक्षकों के पास इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने लायक अंग्रेजी भाषा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।

राज्य सरकार ने अभी-अभी हाल ही में 1300 असिस्टैंट प्रोफेसर रखे हैं जिनमें से बहुत से लोग अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा सकते हैं तथा इसलिये नये कॉलेजों के लिये और शिक्षक लेने की जरूरत नहीं है।

सरकार ने तय किया है कि राज्य में 422 नये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम और खोले जायेंगे। ज्ञातव्य है कि इस समय अंग्रेजी माध्यम के 247 विद्यालय संचालित हैं।

लेकिन आलोचकों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करने में सचेत रहते हुए, प्रतीक्षा करने, देखने तथा उसके बाद कोई टिप्पणी करना बेहतर समझा है। ये लोग अभी बहुत आशंकित है क्योंकि इस समय संचालित 44000 सरकारी विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों में तो मूलभूत सुविधाएं तक भी नहीं हैं।

- यह स्कीम नरेन्द्र मोदी ने चालू की थी, जब वे गुजरात के मु.मंत्री थे तथा अब इस सोच को अपनाने वालों में उत्तर प्रदेश, आंध्र, आदि हैं।
- पर, सभी जगह वो ही दिक्कत सामने आ रही है, जो राजस्थान में आई है, इन नये स्कूल कॉलेजों के लिये अध्यापक कहां से लायें।
- कई राज्यों में, उदाहरण के लिये छत्तीसगढ़ के 44,000 सरकारी स्कूलों में काफी स्कूलों में से अभी बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, नये टीचर्स की नियुक्ति तो दूर की बात है।

रिज़र्व बैंक की चेतावनी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अगस्त। कांग्रेस महासचिव तथा मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने शुक्रवार को सरकार से कहा कि वह आर.बी.आई. के मासिक बुलेटिन में दी गई इस चेतावनी पर ध्यान दे कि

- कांग्रेस ने कहा कि, आर.बी.आई. के मासिक बुलेटिन में दी गई इस चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए कि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से नुकसान हो सकता है।

"पी.एस.बी. (पब्लिक सैक्टर बैंक) के बड़े पैमाने पर निजीकरण से देश का भला होने की बजाय, बुरा ज्यादा होगा।

रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की संख्या 27 से 12 तो पहले ही हो चुकी है और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सी.बी.आई. ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के निवास पर छापा मारा

सिसोदिया, जो आबकारी मंत्री भी हैं, पर आरोप है कि, उन्होंने नयी आबकारी नीति के तहत शराब की दुकान प्राइवेट पार्टियों को देने की मुहिम चालू कर, भारी रकम प्राप्त की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अगस्त। सैंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवैस्टिगेशन (सी.बी.आई.) ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के आवास पर आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों पर रेड डाली। आरोप है कि गत नवम्बर में शुरू हुई इस नीति में प्राइवेट कम्पनियों को शराब के लाइसैंस देने में भारी घोटाला किया गया है।

एक एफ.आई.आर. दर्ज करते हुए सी.बी.आई. ने राष्ट्रीय राजधानी में 20 से ज्यादा स्थानों पर रेड की, सिसोदिया ने ट्वीट किया कि, "सी.बी.आई. मेरे घर पर है। मैं जांच एजेंसी के साथ को ऑपरेट करूंगा। उन्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा।"

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, सी.बी.आई. आ गई है। हम ईमानदार हैं लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जो भी अच्छा काम करता है उसे ऐसे ही सताया जाता है। यही वजह है कि अभी भी हमारा देश न. वन नहीं है।"

सिसोदिया के घर के आसपास धारा 144 लगा दी गयी है और वहां एकत्रित सैकड़ों आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- दिल्ली में इस नयी नीति से पहले शराब की बिक्री केवल सरकारी दुकानों से ही होती थी।
- आप नेता राघव चड्ढा ने कहा, पहले भी सी.बी.आई. ने मु.मंत्री केजरीवाल के घर पर छापा मारा था तथा चार मफलर से ज्यादा कुछ नहीं मिला, अब सिसोदिया के घर से भी पैंसिल, नोट बुक, ज्यॉमैट्री बॉक्स ही मिलेंगे, क्योंकि सिसोदिया शिक्षा मंत्री भी हैं।

35 लाख रू. की लूट

चिड़ावा, 19 अगस्त (निसं)। शहर के पिलानी बाइपास पर श्याम मंदिर के सामने गली में रहने वाले रिटायर्ड फौजी के घर हथियाबन्द लुटेरों ने घुसकर, फौजी को बंधक बनाकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया।

मिली जानकारी कर अनुसार गुरुवार को देर रात, करीब एक बजे के बाद लुटेरे घर में घुसे, उस समय रिटायर्ड फौजी महेंद्र मेघवाल घर में अकेले थे।

लुटेरों ने पिस्तौल दिखाकर फौजी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद लुटेरे कमरों में गहने और रुपए खंगालने लगे। फौजी ने हाथ खोलने की कोशिश भी की। लेकिन बदमाशों ने फौजी को कई थप्पड़ मारे।

बदमाश हिंदी और स्थानीय हरियाणवी -मारवाड़ी बोल रहे थे। लुटेरे करीब 35 लाख रुपए के गहने और 15 हजार रुपए नगद ले गए। बाद में फौजी ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ पैर खोले और पड़ोसी राजेश कुमार डेला को घटना से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस उपाधीक्षक सुरेश शर्मा , सीआई इन्द्रप्रकाश यादव सहित पुलिस जाब्ता वारदात स्थल पर पहुंचा। इसके बाद मोबाइल टीम भी मौके पर आई। डॉग स्क्वॉड टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए।

पीड़ित महेंद्र मेघवाल ने बताया कि लुटेरे करीब पांच थे। सभी स्थानीय लोग ही लग रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं जिसमें कुछ संदिग्ध युवक बाइकों पर नजर आ रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस जांच में जुटी है।

- चिड़ावा में लुटेरों ने एक रिटायर्ड फौजी को बंधक बनाकर करीब 35 लाख रू. के गहने व 15 हजार नकद लूट लिए।

'मछलियों का कोविड टैस्ट करो संक्रमण रोकने के लिये'

चीन हास्यास्पद कदम उठा रहा है, कोविड के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिये

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अगस्त। कहा जाता है कि कोविड के प्रसार को लेकर इतना ज्यादा चिन्तित एवं हताश हो चुका है कि उसने मछुआरों के साथ ही, उनके द्वारा पकड़ी जाने वाली मछलियों की भी कोविड जाँच शुरु कर दी है। चीन के इस कदम का खूब मखौल उड़ाया जा रहा है तथा सोशल मीडिया पर इससे संबंधित चुटकूलों की बाढ़ आ रही है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कुछ टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया है कि चीन जीवित मछलियों की कोविड जाँच कर रहा है ताकि मछुआरों मछलियों को समुद्रों में ही बने रहने दें। मछलियों का महासागर में उनके लिये एक प्रकार का क्वारंटीन ही है।

- राष्ट्रपति शी का कार्यकाल बढ़ाने का मुद्दा तथा उन्हें जीवन पर्यन्त राष्ट्रपति पद देने के लिये, संविधान में परिवर्तन करने का समय आ गया है, कम्युनिस्ट पार्टी की साधारण सभा में।
- इस मौके पर राष्ट्रपति शी का प्रयास है कि, देश में सभी क्षेत्रों में अमन, चैन व समृद्धि का वातावरण दिखे।
- पर, राष्ट्रपति शी के लिये, ज्ञात है कि कठिन समय गुजर रहा है। बैंक बंद होने के कगार पर है, क्योंकि जिन लोगों ने बैंकों से ऋण लिया था, मकान/फ्लैट खरीदने के लिये, बिल्डर उन्हें मकान/फ्लैट उपलब्ध नहीं करा पा रहे, क्योंकि निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। मकान नहीं मिलने के कारण, ऋण लेने वाले ऋण की अदायगी नहीं कर रहे हैं।
- चीन की "इकोनॉमिक ग्रोथ रेट", जिसकी 5.2 प्रतिशत होने की संभावना थी, अब नवीन आकलन में घट कर 3.2 आंकी गई है।

लेकिन चीन की कोविड-नियंत्रण व्यवस्था एक प्रकार से मजाक बनकर रह गई है। कोविड-नियंत्रण एक बहुत बड़ा राजनैतिक मुद्दा बन गया है क्योंकि देश के शीर्ष नेता शी जिनपिंग ने सुस्थापित राजनैतिक परम्परा को उलट दिया है, जिसके अन्तर्गत, सर्वोच्च पद पर बैठे नेता के कार्यकालों की भी प्रतिबंधों द्वारा नियंत्रित होती थी।

शी राजनैतिक व्यवस्था तथा सामान्यजनों के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं पर भी अपनी पकड़ बढ़ा दी है क्योंकि जल्दी ही कम्प्यूनिस्ट पार्टी का अधिवेशन होना है, जिसमें शी को जीवनभर राष्ट्रपति बने रहने के लिये उनके कार्यकाल-विस्तार का समर्थन होना है। इसके लिये सभी मोर्चों पर शान्ति होना जरूरी है।

लेकिन विडम्बना यह है कि सभी मोर्चों पर चीन की स्थिति खराब है। चीन की अर्थव्यवस्था जबरदस्त रूप से पतोन्मुखी होती जा रही है। जनता में प्रॉपर्टी कंपनियों को लेकर बड़े पैमाने पर नाराज़गी है क्योंकि वे उन खरीदारों को भी घर नहीं दे पा रही हैं, जो कर्ज लेकर मकानों की कीमत का भुगतान उन्हें पहले ही कर चुके हैं।

और सबसे बुरी स्थिति कोविड ने कर रखी है जो जंगल की आग की तरह फैलता ही जा रहा है, जबकि पूरे देश में आवागमन पर जबरदस्त प्रतिबंध लगे हुये हैं तथा "नो-कोविड" नीति पूरी सख्ती के साथ अमल में लाई जा रही है जिसकी देख-रेख तथा नेतृत्व स्वयं शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। लेकिन तथ्य यह है कि इसे सीमित एवं समाप्त करने के तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद, महामारी फैलती ही जा रही है।

इससे शी की व्यक्तिगत छवि एवं पकड़ प्रभावित हो रही है। हाँगकाँग में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

7 लाख रू. का मुआवजा

जयपुर, 19 अगस्त (का.सं.)। रेलवे दावा अधिकरण ने, सफर के दौरान ट्रेन से गिरकर घायल होने के मामले में रेलवे को जिम्मेदार माना और रेलवे को आदेश दिए कि वह ट्रेन से गिरकर घायल हुए यात्री को सात लाख बीस हजार रुपए की हर्जाना राशि नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करे। अधिकरण ने यह आदेश लियाकत की क्लेम याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हरिशंकर गौड़ और अधिवक्ता नम्रता शर्मा ने बताया कि प्रार्थी आठ जुलाई, 2019 को हिसार-जयपुर पैसेंजर ट्रेन में बावल से अलवर की यात्रा कर रहा था। इस दौरान पड़ीसल स्टेशन के नजदीक वह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- रेल्वे दावा अधिकरण ने यात्रा के दौरान ट्रेन से गिरे यात्री के लिए रेल्वे को जिम्मेवार माना तथा उक्त यात्री का 7.20 लाख रू. का हर्जाना देने के आदेश दिए।